भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2907

उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

इंटरनेट सुविधाएं

2907. श्री मलूक नागर:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का उन लोगों को नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का विचार है जो इसकी लागत वहन करने में सक्षम नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त योजना देश के विभिन्न हिस्सों में कब तक लागू की जाएगी?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ङ) पिछले 10 वर्षों में भारत में दूरसंचार कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है।

- इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर सितंबर, 2023 में 91.82 करोड़ हो गई है।
- बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशन (बीटीएस) की संख्या मार्च, 2014 में 6.49 लाख से बढ़कर मार्च, 2023 में 25.42 लाख हो गई है।

- 14 महीनों में 738 जिलों में लगाए गए 4 लाख से अधिक बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशन (बीटीएस) के साथ विश्व में तीव्रतम 5जी सेवाओं के रोलआउट में भारत का स्थान अग्रणी है।
- मोबाइल ब्रॉडबैंड की मीडियन स्पीड भी मार्च, 2014 में 1.30 एमबीपीएस से बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 75.80 एमबीपीएस हो गई है।
- **इसके साथ-साथ डेटा का मूल्य मार्च, 2014 में 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर मार्च, 2023 में 9.94 रुपये प्रति जीबी हो गई है।**

इसके अलावा भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है:-

- भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। दिनांक 13.11.2023 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 2,07,346 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा भारतनेट का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायतों (जीपी) से बढ़ाकर सभी बसे हुए गांवों तक कर दिया गया है।
- सितंबर 2023 तक देश के 6,44,131 गांवों (गांवों के आंकड़े भारत के महापंजीयक के अनुसार है) में से लगभग 6,16,300 गांवों में 95.7% की कवरेज के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध हैं।
- देश के सेवा से वंचित गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं। सरकार ने 41,331 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 54,000 से अधिक गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश के सेवा से वंचित क्षेत्रों में 41,160 टावर लगाने के लिए योजना बनाई है।
- दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार 7,535 गांवों को कवर करते हुए देश में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीमों में कुल 6,394 मोबाइल टावर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

*****